जनजातीय विकास परिषद, जनजातीय विकास मंच द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन

भोपाल। जनजाति समाज की महान परंपराएँ रही हैं जिसकी वजह से भारत में सबसे सम्पन्न गोंडवाना राज्य स्थापित था, जिसमें एक से बढकर एक वीर, देशभक्त, स्वतंत्रताप्रेमी रानी दुर्गावती, बिरसामुण्डा, शंकरशाह, रघुनाथ शाह, जैसे महान देशभक्त व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मुगलों, अँग्रेजों से स्वतंत्रता अपने राष्ट्र के लिये कुरबानियाँ दी हैं, अपना सर्वस्व देश पर अर्पित कर दिया था। हम ऐसे महान व्यक्तियों की संतान हैं, हमारी परंपराएँ, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, अभूतपूर्व रहे हैं। हमें उनके रास्ते पर चलकर पुनः अपने आपको देशभक्त नागरिक साबित करना है। इसके लिए आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। उक्ताशय के उद्गार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनसुईया उइके ने कहे। सुश्री उइके राजधानी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुख्यालय भवन के सभागार में जनजातीय विकास मंच द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। इस कार्यशाला में मध्यप्रान्त के 9 प्रदेशों के जनजातीय जन प्रतिनिधियों एवं जिला प्रमुखों, विधायकों, मंत्रियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ के मंत्री केदार कश्यप, केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते एवं जनजातिय विकास मंच के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ साथ करीब 100 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में जनजातियों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिये पेशा एक्ट, फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुविधा लेने वाले गैर आदिवासियों, धनगढ एवं अन्य चार जातियों को सूचीबद्ध करने, आदिवासी कला, सँस्कृति, भाषा, धर्म को जीवित रखने पर भी गहन चिंतन कर प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया। इस अवसर पर सुश्री उइके द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, के संबंध में विस्तार से जनजाति प्रतिनिधियों को जानकारियाँ से अवगत कराते हुए अपने अधिकारों का हनन होने पर आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के संबंध में विधि प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, कुछ प्रमुख समस्याएँ जो कि आयोग के समक्ष विचाराधीन है उनके माध्यम से उदाहरणों के साथ समझाईश दी गई।

बीएड कॉलेज संचालक बोले-

आदिवासी विकासमंच भोपाल में आयोजित कार्यशाला के समाचार

है पर शासन के निर्देश न मिलने के चलते ये कुछ भी नहीं बता पा रहे।

डिजिटलाइजेशन होगा। फोटो के रुप में पेश साक्ष्यों का भी डिजिटलाइजेशन होगा।

जनजातीय सुरक्षा मंच के सम्मेलन में बोले नेता

अपनी अलग पहचान बनाएं आदिवासी' धर्मांतरण से बचें

जनजातीय सुरक्षा मंच ने यह सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में आदिवासियों की एकता, विकास और उनसे जुड़े अन्य मसलों पर बात हुई है।

■ फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

राजनीतिक संवाददाता, भोपाल

अपने अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद के जरिए आदिवासियों के लिए काम रहे संघ ने आदिवासियों पर डोरे डालने के लिए भोपाल में जनजाती सम्मेलन का आयोजन किया पर इसमें कुछ आदिवासी नेताओं ने अपनी अलग पहचान बनाने की नसीहत आदिवासियों को देकर संघ नेताओं को चौंका दिया है। हालांकि परिषद के नेता इस तरह की किसी बात से इंकार कर रहे हैं।

संघ से जुड़ी संस्था वनवासी कल्याण परिषद सालों से आदिवासियों के लिए काम कर रही है। इस संस्था ने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर वनवासी कल्याण परिषद ने दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में आदिवासियों के विकास और उनकी एकता पर बात होनी थी।

सूत्रों की मानें तो सम्मेलन में कुछ नेताओं ने धर्म परिवर्तन का तो खुलकर विरोध किया पर इशारों ही इशारों में आदिवासियों को अपनी अलग पहचान बनाने की भी नसीहत दे डाली। सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके विधायक रामलाल रौतेल समेत कई नौकरशाह भी मौजूद थे।

हिंदू हैं आदिवासी

दूसरी तरफ वनवासी कल्याण परिषद के महामंत्री योगीराज परते ने कहा कि सम्मेलन में आदिवासियों के विकास पर बात हुई। आदिवासी हिंदू हैं। सम्मेलन में हिंदुओं के उनसे अलग होने संबंधी कोई बात नहीं हुई और न ही इस तरह की चर्चा हुई। वहीं परिषद के नेता गोविंद कुंडल ने भी इस तरह की बातों को खंडन करते हुए कहा कि वहां तो भगवान राम को लेकर भी चर्चा हुई है।

शिक्षा पर रहा जोर

राजधानी के दत्तोपंत ठेगड़ी भवन में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हुए इस सम्मेलन में आदिवासियों से अपनी अलग पहचान बनाने के साथ शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर जोर देने को कहा गया तो बदलते सामाजिक परिवेश के हिसाब से कुरीतियों से बचने की भी सलाह दी गई। गौरतलब है कि संघ आदिवासियों के धर्मान्तरण को लेकर अभियान चला रहा है। सूत्रों की माने तो संघ के निर्देश पर ही भाजपा के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन में महाकोशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, विंध्य, मालवा समेत कई अंचलों के नौकरीपेशा, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय मंत्री कुलस्ते कल सीएम के साथ विमान से भोपाल आए थे और सम्मेलन में शामिल होकर आज सुबह ही दिल्ली रवाना हुए हैं।

खड़गपुर की कमेटी ने शुरू किया काम

नर्मदा में खनन पर पहली रिपोर्ट

आदिवासी विकासमंच भोपाल में आयोजित कार्यशाला के समाचार

दैनिक जबलपुर [illegible], जबलपुर

20 JUN 2017

आदिवासियों को मिलेगा न्याय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष ने सुनी समस्याएं, निपटाए मामले

छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके ने सर्किट हाउस में आदिवासियों के विभिन्न मामलों में सुनवाई की और उन्हें न्याय दिलाने कुछ मामले आयोग में रजिस्टर्ड कर अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाने को कहा वहीं मुआवजे को लेकर आई शिकायतों का भी निराकरण किया। आयोग की उपाध्यक्ष के पास सुनवाई के लिये जिले भर से आदिवासी आए और उन्होने अपनी मांग रखी। धनकशा खदान में जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा के साथ डब्ल्यूसीएल द्वारा परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दिए जाने की शिकायत लेकर आदिवासी पहुंचे, इसमें आयोग में प्रकरण दर्ज किया गया और आगामी दिनों में सुनवाई के लिए डब्ल्यूसीएल के अधिकारियों को उपाध्यक्ष तलब कर मामले का निपटारा करेंगी। छिंदी में आदिवासी हरिप्रसाद द्वारा हाउसलोन में रिश्वत मांगने की ग्रामीण बैंक की शिकायत की जिसमें भी सुनवाई की गई। गुंडेरा अहीर जाति के लोग आदिवासी में आते हैं। जिले में गुंडेरा अहीर जाति के आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया। अमरवाड़ा विकासखण्ड क्षेत्र में बन रहे केकड़ा जलाशय में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा नहीं देने की मांग लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी आयोग की उपाध्यक्ष के पास पहुंचे। उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके ने इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी मांगेगी। आदिवासियों ने अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत भी आयोग की उपाध्यक्ष को की। जिनके आवेदन में सुनवाई की और मामले निपटाए। आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री उईके ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आदिवासियों की समस्याएं सुनी।

आगामी दिनों में बैठेगी बैंच

बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के आदिवासियों की समस्या निपटाने के लिए छिंदवाड़ा में अनुसूचित जनजाति आयोग की बैंच भी बैठेगी। बैंच आदिवासियों की सभी समस्याओं का निपटारा करेगी। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की बैंच बैठने से बड़ी संख्या में आदिवासियों के मामले निपटेंगे।

छिन्दवाडा स्थित स्थानीय विश्राम भवन में आम नागरिकों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए

दैनिक भास्कर छिन्दवाड़ा

2 0 JUN 2017

आदिवासियों की सुनी समस्याएं

एसटी कमीशन उपाध्यक्ष ने लगाई चौपाल

एसटी कमीशन उपाध्यक्ष को ज्ञापन देते ग्रामीण।

छिंदवाड़ा। अनसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उईके ने सोमवार को चौपाल लगाकर आदिवासियों की समस्याएं सुनी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए पीड़ितों ने सुश्री उईके के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जिसमे से अधिकांश समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। सर्किट हाउस में चौपाल लगाने के बाद अधिकारियों से समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त एनएस बरकड़े सहित अधिकारी मौजूद थे।

ये आई समस्याएं

- गोंडेरा अहीर समाज के लोगों ने सुश्री उईके के समक्ष समस्याएं रखते हुए गुंडेरा समाज का नाम अहीर जाति में दर्ज किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुंडेरा समाज आदिवासी के अंतर्गत आता है, लेकिन पटवारियों द्वारा इसे अहीर जाति में दर्ज किया जा रहा है।
- धनकसा भूमिगत खदान के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने का मामला सामने आने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष ने आदिवासी को उचित मुआवजा देने और नौकरी प्रदान करने के आदेश डब्ल्यूसीएल प्रबंधन को दिए हैं।
- छिंदी के स्थानीय लोगों ने सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

दैनिक पत्रिका, जबलपुर
8 JUN 2017

जागृति सम्मेलन

आदिवासी समाज को जागरूक करने की जरूरत

अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुइया उइके ने कहा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

पांढुर्ना. पूरे देश में आदिवासी समाज की संख्या सबसे अधिक है। इनके विकास के साथ ही संरक्षण के लिए सरकार ने संविधान में कड़े क़ानून बनाए है परंतु इनका पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण आदिवासियों को अपना हक़ पाने के लिए साल-साल भर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते है। आज यदि वास्तविकता में हमें आदिवासी समाज को आगे लाना है तो समाज को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना होगा।

उक्त आशय के विचार अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर संत रविदास भवन में आयोजित जागृति सम्मलेन में रखें। उन्होंने अपने आयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की उपाध्यक्ष को मजिस्ट्रीयल पॉवर दिए गए है कि सीधे हम अधिकारी को नोटिस देकर पूछ सकते है कि आखिर आदिवासी के साथ घटित अपराध पर क्या करवाई हो सकी है। इस मौके पर आदिवासियों के लिए बनने वाले समाज भवन की भूमि को लेकर चल रहे विवाद को सम्मेलन में उठाया गया। गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह कुसरे ने कहा कि हमने सिर्फ भूमि मांगी थी। प्रशासन पहले भूमि दिखाकर आबंटित करने का आश्वासन दिया और फिर एक भी आपत्ति नहीं आने के बावजूद आबंटन पर रोक लगा दी गई।

संजय परतेती ने भवन के भूमि प्राप्त करने हर तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही। नपा अध्यक्ष मीनाक्षी खुरसंगे ने आदिवासी समाज के लिए नगर पालिका द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामराव कवड़ेती, जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश पदमाकर, पार्षद इरशाद कुरैशी, राजू रेवतकर, रंजना आहके, रंजना कुमरे, वासुदेव कुमरे, दुर्गेश उइके, यादवराव डोबले, आकाश सरसे, तरुण खोडे, ईश्वर कावड़ेती, फूलसिंह उइके आदि उपस्थित थे।

गोंडवाना महासभा युवाफ्रॅट पान्ढुर्ना के सॉस्कृति कार्यकम में

दैनिक लोकमत समाचार नागपुर
18 JUN 2017

आदिवासी भवन और समाज के लोगों को उनका हक दिलाऊंगी : अनुसुइया

आदिवासी समाज का भवन नहीं बनने से खफा हुईं आयोग की उपाध्यक्ष

पांढुर्णा । 17 जून । लोस सेवा

'पांढुर्णा विधानसभा को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया है. यहां सबसे ज्यादा आदिवासी समाज निवासरत है. यहां जनप्रतिनिधि हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पांढुर्णा आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भवन नहीं है. यही नहीं, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. वे अपने हक के लिए भटक रहे हैं. बाहुबली लोग आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं. पुलिस आदिवासियों पर शराब के झूठे मामले बना रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पांढुर्णा में आदिवासी भवन भी बनेगा और समाज के पीड़ितों को उनका हक भी दिलाऊंगी. इसलिए ही मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने आयोग का उपाध्यक्ष की कमान सौंपी है.'

आज यह बात पांढुर्णा रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुइया उइके ने कही . इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष राजू रेवतकर, दादा धर्माधिकारी, श्याम धुर्वे सहित भाजपाई उपस्थित थे.इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के हर ब्लॉक में आदिवासी समाज की बैठक लेकर उन्हें आयोग की जानकारी दी जाएगी.

संत रविदास भवन में कैलेंडर का विमोचन करतीं आयोग की उपाध्यक्ष और नपा अध्यक्ष.

नांदनवाड़ी क्षेत्र का विकास का रखा मुद्दा

पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने पूछा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहेजाने वाले नांदनवाड़ी के अंतर्गत लगभग 60 गांव आते हैं लेकिन यहां नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने के बावजूद अधिकारी पदस्थ नहीं है. किसान पांढुर्णा आकर तहसील कार्यालय में काम करते है. यहां 30 बिस्तर वाला अस्पताल है, जहां केवल एक डॉक्टर पदस्थ है. इस अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष नहीं है, जिससे परिजनों को 60 से 70 किलोमीटर पांढुर्णा आकर लाश का पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है. इन मुद्दों पर उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे इन समस्याओं पर सबसे पहले ध्यान देंगी.

आदिवासी समाज ने किया उपाध्यक्ष का सत्कार

संत रविदास भवन में आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुइया उइके का सत्कार किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज का उत्थान, उनकी सुरक्षा और सम्मान तब मिलेगा, जब सब एकजुट होकर समाज के लिए कार्य करेंगे. वहीं, नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी सुरसंगे ने कहा कि आदिवासी समाज का भवन होना चाहिए. इसके लिए वे जो भी प्रयास होंगे वे करेंगी. इस दौरान जनपद अध्यक्ष गणेश पद्माकर, रामराव कवडेती, प्रहलाद कुमरे, संजय परतेती, रंजना कुमरे सहित समाज के लोग उपस्थित थे.

पान्दुर्ना में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन

किश्त की राशि देने बैंक अधिकारी मांगते हैं रिश्वत

● एसटी आयोग उपाध्यक्ष के पास पहुंची शिकायत

दिव्य एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा।

गरीब परिवार को छत मुहैया कराने सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। किन्तु भ्रष्ट अधिकारी शासन के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। योजना में पारदर्शिता लाने और गरीबों तक लाभ पहुंचाने भले ही सख्त नियम बनाया गया है। बावजूद इसके गरीब हितग्राहियों को बगैर रिश्वत के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सोमवार को केन्द्रीय

एसटी आयोग उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा लगाई गई बैठक में खुलकर सामने आया स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में करीब 2 दर्जन आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। किन्तु ज्यादातर आवेदनों ने बैंक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा लागू मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दोनों ही योजनाएं बैंक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हिर्री निवासी हरिप्रसाद पिता बलराम [illegible] ने आवेदन सौंप बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना करने के एवज में बैंक मैनेजर कृष्णकांत अवस्थी द्वारा 10 हजार रुपए की मांग की जा रही है।

पैसे नहीं देने की वजह से महीनों गुजर जाने के बाद भी लाभ नहीं मिला है। जबकि शिकायत करने पर बैंक मैनेजर व कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जाती है। हरिप्रसाद ने बताया कि बैंक मैनेजर द्वारा अन्य हितग्राहियों से भी रिश्वत वसूली गई है।

पीएम आवास में भी वसूली

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी वसूली की शिकायत मिली है। ग्राम पंचायत [illegible] के ग्रामीणों ने बताया कि बैंक शासन द्वारा योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रुपए जारी किया गया। किन्तु बैंक मैनेजर द्वारा सभी हितग्राहियों से एक-एक हजार रुपए की वसूली कर ली गई। अतः हितग्राहियों को 39 हजार रुपए ही मिले है। सभी हितग्राहियों से एक एक हजार रुपए की वसूली की गई है।

ये भी पहुंची शिकायतें

● पेंचढ़ा जलाशय निर्माण में प्रभावित आदिवासी किसानों की जमीन डूब में फंस रही है। किसानों को नहर के पास ही सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाए, साथ चार गुना मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

● गोंड अहीर समुदाय के लोगों का राजस्व अभिलेख में त्रुटि से अहीर जाति दर्ज होने से स्थानीय स्तर पर सूक्ष्मता से जांच कराकर राजस्व अभिलेख में सुधार हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश प्रसारित कराया गया।

● धनकसा भूमिगत कोल खदान हेतु भूमि देने वाले किसान परिवार के सदस्यों को नौकरी एवं चार गुना मुआवजा दिलाया जाए।

दिव्य एक्सप्रेस
20/6/2017

गुहार...

आयोग उपाध्यक्ष के सामने निकल पड़े पीड़ितों के आंसू

प्रधानमंत्री आवास की किस्त के लिए मांगी रिश्वत, धनकशा खदान में मांगी नौकरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

छिंदवाड़ा . राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुइया उइके के सामने सोमवार को अपनी पीड़ा सुनाते-सुनाते आदिवासियों के आंखों से आंसू निकल पड़े। उइके ने सर्किट हाउस में पीड़ितों को सुना और आयोग की ओर नोटिस समेत समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ग्राम [illegible] के रामकुमार, [illegible] समेत अन्य ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि प्रधानमंत्री आवास की किस्त निकालने के नाम पर बैंक कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। पहले भी 40 हजार रुपए की किस्त में पैसे दे चुके हैं। पैसे न देने पर उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है। दूसरी शिकायत ग्राम [illegible] के [illegible] सरयाम ने की और बैंक कर्मचारी की दस हजार रुपए मांगने की शिकायत की। ग्राम रंगीनखापा के [illegible] धुर्वे ने गोंडेरा अहीर जाति के लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अहीर दर्ज होने पर सुधारने की मांग की। उनका कहना था कि प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन अभी तक सुधारा नहीं गया है। आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि वे सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस देकर बुलाएंगी और न्याय करवाएंगी।

मांग... आयोग उपाध्यक्ष से शिकायत करते हुए ग्रामीणजन।

खदान में मांगी नौकरी और मुआवजा

धनकशा [illegible] संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आयोग उपाध्यक्ष से मुलाकात की और धनकशा खदान में अधिग्रहित जमीन के बदले [illegible] के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। इसी तरह अमरवाड़ा के ग्राम [illegible] के [illegible] ने जलाशय निर्माण में अधिग्रहित जमीन का चार गुना मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि [illegible] को [illegible] के पट्टे, विद्युत पोल और [illegible] [illegible] सिस्टम लागू करने की मांग पूरी करना चाहिए।

पत्रिका 20/6/2017

दैनिक नवभारत छिंदवाड़ा

20 JUN 2017

केकड़ा जलाशय

छिंदवाड़ा. सिंचाई विभाग द्वारा बिना मुआवजा दिए केकड़ा जलाशय निर्माण का किसानों ने विरोध करते हुए अजजा आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुईया उईके को दिया ज्ञापन.

ग्राम केकडा के नागरिक ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए